प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

सभी पाठकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | वर्ष : 61 अंक 06 30 जनवरी 2025 पृष्ठ-12 मूल्य - 3.00

प्रकाशन के 6 दशक

INDIA गठबंधन की कब्र पर खड़ा होगा तीसरा मोर्चा?

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो राजनीतिक बयानबाजियां होती दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि जहां 'इंडिया गठबंधन' अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वहीं 'एनडीए गठबंधन' पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके अलावा, एक खास लक्षण यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय राजनीति में कभी कद्दावर समझा जाने वाला कांग्रेस-भाजपा विरोधी तीसरा मोर्चा एक बार फिर से अपना नया आकार ग्रहण कर रहा है।

कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा...

कैप्टन बदलने के पक्ष में इंडिया गठबंधन के कई खिलाड़ी!

तीसरा मोर्चा कैसा होगा... इसकी तस्वीर अभी धुंधली... विशेष रिपोर्ट पेज-6-7-8

मोहन सरकार का फैसला...

17 धर्म क्षेत्रों में शराब बेचने पर पाबंदी

कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी पेज- 2

मध्य प्रदेश के कई आईएएस के पास नहीं है फूटी कौड़ी तो.... कई हैं धन कुबेर

31 जनवरी तक बताना होगा कि कितनी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की पेज- 3

केजरीवाल से आतिशी तक आम आदमी पार्टी दिग्गजों को घर में बीजेपी-कांग्रेस ने घेरा!

पेज- 9

बीजेपी को दिल्ली चुनाव के बाद मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

अगला कौन ?

पेज- 5

मिल्कीपुर सीट पर योगी और अखिलेश की सियासी टक्कर

बीजेपी में बगावत की बू, सपा भी अछूती नहीं, चंद्रशेखर से बिगड़ेगा खेल? पेज- 10

लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का,
बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं है।

तेजस्वी यादव को लालू ने सौंप दी विरासत

राजद में टूट होने पर पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न और झंडे को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय मान्य नहीं होगा पेज- 11

मोहन सरकार का फैसला...

17 धर्म क्षेत्रों में शराब बेचने पर पाबंदी

शराब दुकानें 20 फीसदी महंगी होंगी, कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी

भोपाल। मप्र सरकार ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सहित प्रदेश के 13 शहरों और 4 ग्रामीण क्षेत्रों में अगले वित्तीय वर्ष से शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इन स्थानों पर मौजूद सभी शराब दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। हालांकि इन धर्म क्षेत्रों में पीने और रखने पर रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति-2025 को मंजूरी दी गई, जिसमें यह फैसला लिया गया ।सीएम ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे प्रदेश को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएगी। पहले चरण में 17 स्थानों की शराब दुकानें बंद की जाएंगी, जिन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

नई शराब नीति के तहत भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में रेस्तरां रिसार्ट और सिविल क्लब के लिए नई कैटेगरी का लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए सामान्य बार के मुकाबले 50% फीस देनी होगी। यहां बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक बेचने की अनुमति होगी। किसी भी तरह की हार्ड ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। नर्मदा नदी के दोनों तटों से 5 किमी की दूरी तक लागू शराबबंदी की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

एमपी में अब 90 एमएल बॉटल में मिलेगी देसी शराब

नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के आवंटन मूल्य में 20 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहीं देसी शराब को 90 और 180 एमएल की बॉटल में बेचा जाएगा ।महेश्वर में देवी अहिल्या बाई की 300वें जयंती वर्ष के मौके कैबिनेट बैठक की गई। नई आबकारी नीति में कहा है कि शराब दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2025-26 में करके ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी ।प्रदेशभर में कुल 47 शराब दुकानें बंद होंगी। इनमें से 17 उज्जैन की हैं। आबकारी विभाग के अनुसार, इससे लगभग 500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला भी लिया है। कुल 17 स्थानों की 47 शराब दुकानों को एक अप्रेल 2025 से बंद किया जाएगा। इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ की राजस्व क्षति होगी ।सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। इसके लिए 80 प्रतिशत या अधिक राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। फिर लाटरी के जरिए और इसके बाद ई टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा।

बार की नई कैटेगरी उत्तराखंड से अपनाई, लाइसेंस फीस आधी होगी

शराब दुकानों का नवीनीकरण मौजूदा वार्षिक मूल्य में 20% की वृद्धि के साथ किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी और फिर ई-टेंडर की प्रक्रिया होगी। जिले की 80% दुकानों का नवीनीकरण तभी मंजूर किया जाएगा, जब 20% की वृद्धि पर सहमति होगी। अगर सहमति नहीं बनी, तो ई-टेंडर किए जाएंगे ।बार की नई कैटेगरी उत्तराखंड से अपनाई गई है। कुन बार के लिए नियम वही रहेंगे, जो पहले से मौजूद हैं। हालांकि, इस नई कैटेगरी की लाइसेंस फीसआधी होगी। इनमें केवल वही ड्रिंक्स परोसी जाएंगी, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10% से कम होगी ।देसी शराब में अल्कोहल की मात्रा घटाने के लिए 60 डिग्री (अंडर प्रूफ) की नई कैटेगरी शुरू की गई है। यह 180 एमएल के साथ 90 एमएल की नई पैकिंग में भी उपलब्ध होगी। शराब दुकानों पर बिलिंग केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से की जाएगी ।मप्र में वर्तमान में कुल 450 बार हैं। नई नीति लागू होने के बाद बार की संख्या दोगुनी हो सकती है।

पिछले 5 साल में शराब से कमाई

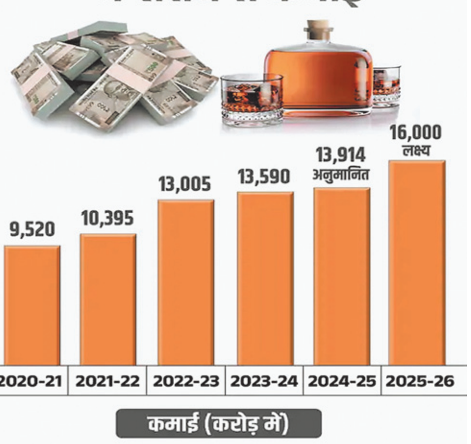

एमपी में दो दशक में 37 फीसदी बढ़ गई शराब दुकानें

2005	2025
दुकानों की संख्या 2270	दुकानों की संख्या 3605 ग्रामीण क्षेत्र- 2151 शहरी क्षेत्र- 1454

शराब कारोबार में ई-चालान और ई बैंक गारंटी ही मान्य

विदेशी शराब वेयर हाउस की सप्लाई व्यवस्था का ऑटोमेशन किया जाएगा और वेयरहाउस के स्मार्ट वेयर हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। विदेशी शराब की ड्यूटी दरों को ईडीपी आधारित एड वेलोरेम किया जाएगा। वहीं शराब के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने अब सिर्फ ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी और एफडी मंजूर नहीं होगी।

नई श्रेणी के रूप में बार शुरू होगा

सरकार ने तय किया है कि युवाओं में शराब की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और शराब को हतोत्साहित करने के लिए नई श्रेणी बार के रूप में शुरू की जाएगी। इसमें सिर्फ बीयर, वाइन और आरटीडी बेची जा सकेगी। इसके लिए हर जिले में आबकारी विभाग के अधिकारी व्यवस्था तय कराएंगे।

शराब दुकानों में पीओएस मशीनें लगेंगी

आबकारी नीति में कहा है कि सभी शराब दुकानों पर पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीनें लगाई जाएगी। इसी से सप्लाई और बिलिंग होगी। दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा ।अवैध शराब की बिक्री रोकने देसी शराब में कम तेजी की 60 डिग्री नई श्रेणी प्रारंभ की जाएगी। देसी शराब 180 एमएल और 90 एमएल की बोतलों में बिकेगी। 180 एमएल की केपिसिटी में टेट्रा पैक भी शुरू किया जाएगा।

यहां की शराब दुकानें और बार होंगे बंद

मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद नई आबकारी नीति के अंतर्गत उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक नगरीय क्षेत्रों की शराब दुकानों और बार को बंद किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत बांदकपुर, सलकनपुर, कुंडलपुर, बरमान कलां, लिंगा, बरमान खुर्द की शराब दुकानों और बार को पूरी तरह बंद किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के कई आईएएस के पास नहीं है फूटी कौड़ी तो....

कई हैं धन कुबेर

31 जनवरी तक बताना होगा कि कितनी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की

एमपी के भूमिहीन कलेक्टर

जगह	कलेक्टर
इंदौर	आशीष सिंह
खंडवा	अनूप कुमार सिंह
बुरहानपुर	भव्या मित्तल
देवास	ऋषभ गुप्ता
शाजापुर	ऋजु बाफना
मुरैना	अंकित अस्थाना
रीवा	प्रतिभा पाल
अनूपपुर	हर्षल पंचोली
निवाड़ी	लोकेश जांगिड़
नरसिंहपुर	शीतला पटले

भोपाल। कहा जाता है कि यदि किसी जिले में सबसे पॉवरफुल व्यक्ति कोई होता है, तो वह उस जिले का कलेक्टर है। प्रशासनिक अधिकारी के नाते शानदार सैलरी, तमाम सुख-सुविधाएं, घर-गाड़ी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कलेक्टर के पास एक इंच भी अचल संपत्ति न हो। मध्य प्रदेश में ऐसे एक-दो नहीं, बल्कि 10 कलेक्टर हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में एक इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं, जिन्हें गिफ्ट या फिर विरासत में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। इसका खुलासा आईएएस अधिकारियों द्वारा कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय को दी गई अचल संपत्ति की जानकारी से हुआ है। इस सूची में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी समझे जाने वाले शहर इंदौर के कलेक्टर का भी नाम है। आइए बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन-कौन से कलेक्टर भूमिहीन है।

मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पदस्थ कलेक्टरों ने अभी तक जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीदा। इसमें 2010 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी हैं। इंदौर के पहले वे भोपाल में कलेक्टर और इंदौर-उज्जैन में नगर निगम कमिश्नर रहे हैं। वे एक फेमस क्विज शो के कर्मवीर एपिसोड में हॉटशीट पर भी बैठे थे और उन्होंने इस शो में 12 लाख रुपए जीते थे। डीओपीटी को दी गई वार्षिक जानकारी में बताया कि 'मध्य प्रदेश और देश में उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।' खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। वे ग्वालियर और जबलपुर में अपर कलेक्टर रहे हैं। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी में बताया कि 'उनके पास किसी भी राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसके पहले वे नीमच में जिला पंचायत सीईओ और धार में एसडीएम रही हैं। अप्रैल 2023 में वे दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं।'

देवास कलेक्टर और 2014 बैच के आईएएस ऋषभ गुप्ता के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। देवास कलेक्टर के पहले ऋषभ गुप्ता इंदौर स्मार्ट सिटी में सीईओ रहे हैं। सीईओ रहते उनके द्वारा किए गए काम को लेकर उन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में अवार्ड मिला था ।शाजापुर कलेक्टर और 2014 बैच की आईएएस अधिकारी ऋजु बाफना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी ऋजु नरसिंहपुर कलेक्टर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वे भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त, सिंगरौली में एडीएम, उज्जैन में एडीएम, जबलपुर में जिला पंचायत सीईओ भी रह चुकी हैं। मुरैना में कलेक्टर और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अंकित अस्थाना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। भोपाल के रहने वाले अस्थाना भोपाल स्मार्ट सिटी में सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा शिवपुरी में बतौर एसडीएम भी पदस्थ रहे हैं। उनके मां और पिता दोनों भोपाल में सीनियर डॉक्टर हैं। रीवा कलेक्टर और 2012 बैच की आईएएस अधिकारी प्रतिभा पाल के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। रीवा कलेक्टर के पहले वे लंबे समय तक इंदौर नगर निगम कमिश्नर भी रहीं हैं ।अनूपपुर कलेक्टर और 2015 के आईएएस अधिकारी हर्षल पंचोली के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे पूर्व में एसडीएम पेटलावाद, टीकमगढ़ और अनूपपुर में जिला पंचायत सीअई रहे हैं। भोपाल में अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं। आईआईटी कानपुर से पासआउट हर्षल मूलत: उज्जैन के रहने वाले हैं ।निवाड़ी कलेक्टर और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश जांगिड़ मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे इसके पहले बड़वानी में अतिरिक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं। वे कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। 2014 बैच की आईएएस शीतला पटले अभी नरसिंहपुर कलेक्टर है। उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे इसके पहले छिंदवाड़ा कलेक्टर भी रह चुकी हैं। वह मध्यप्रदेश की बालाघाट की रहने वाली है।

एमपी के आईएएस और आईपीएस कितने मालदार....

31 जनवरी को पता चलेगा कौन रखता है कुबेर का खजाना

प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा कि उन्होंने पिछले एक साल के भीतर राज्य और राज्य के बाहर कितने अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की है। इसके साथ अब उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उसकी कीमत कितनी है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा एक जनवरी की स्थिति में संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके साथ ही ऑनलाइन जमा की गई जानकारी का प्रिंट आउट सामान्य प्रशासन विभाग में भी जमा कराएं। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तरह कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा ।आईएएस अधिकारियों के अलावा आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को स्वयं, पत्नी और बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति बतानी होगी। आईएएस, आईपीएस अधिकारियां के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अचल संपत्ति खरीदने के लिए विभाग प्रमुख को दी गई जानकारी, पूर्व में ली गई अनुमति के अलावा उपहार में परिजनों और रिश्तेदारों से मिली अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी।

कलेक्टर को कितना मिलता है वेतन

अब आपको बताते हैं कि आईएएस बनने के बाद और एक कलेक्टर को कितनी तनख्वाह और सुख-सुविधाएं मिली हैं। एक आईएएस अधिकारी का न्यूनतम वेतन 56 हजार 100 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। यह वेतनमान तब मिलता है, जब आईएएस बनने के बाद वह प्रोवेशनल पीरियड में होते हैं और जिले में उन्हें एसडीएम या सहायक आयुक्त बनाया जाता है। हालांकि यह मूल वेतन होता है, इसमें टीए, डीए और एचआरए शामिल नहीं है। जब उन्हें 5 से 8 साल का अनुभव हो जाता है और वे एडीएम, उप सचिव या अवर सचिव बन जाते हैं, तो उनका मूल वेतन 67 हजार 700 पहुंच जाता है ।9 से 14 साल के अनुभव होने और जिले में कलेक्टर बनने पर उनका मूल वेतन 78 हजार 800 से लेकर 1 लाख 18 हजार 500 रुपए तक हो जाता है। इस समय अवधि में उन्हें जूनियर स्केल श्रेणी में आईएएस ग्रेड पे के रूप में 5400 रुपए, वरिष्ठ समय स्केल में 6600 आइएएस ग्रेड पे, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड या 9 साल का अनुभव होने पर आईएएस ग्रेड पे के रूप में 7600 रुपए और चयन ग्रेड यानी 12 से 15 साल का अनुभव होने पर आईएएस ग्रेड पे के रूप में 8700 रुपए अलग से मिलते हैं।

9 कलेक्टरों को गिफ्ट और विरासत में मिली प्रॉपर्टी

वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद तो प्रॉपर्टी न खरीदी हो, लेकिन गिफ्ट और विरासत में जरूर इन्हें संपत्ति मिली है। ऐसे करीबन 9 कलेक्टर हैं। इनमें विरासत में संपत्ति पाने वालों में सबसे आगे सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच का नाम है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच को राजस्थान बीकानेर में विरासत में करीबन 69 एकड़ भूमि विरासत में मिली है। इसके अलावा उनकी पत्नी को करीबन 5 एकड़ भूमि और 23सौ वर्ग फीट का प्लॉट गिफ्ट में मिला है। हालांकि अचल संपत्ति के विवरण में इसकी कीमत नहीं बताई गई ।धार कलेक्टर और 2013 बैच के अधिकारी प्रियंक मिश्रा को लखनऊ में पिता से 1।76 करोड़ रुपए कीमत का विरासत में मकान मिला है। हालांकि उन्होंन अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी ।झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी मां ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है। उन्हें गिफ्ट में राजस्थान में 1800 स्क्वायर फीट का मकान, 1 हजार वर्गफीट पर निर्मित मकान मिला है। नेहा मीणा ने भी अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी ।भिंड कलेक्टर और 2011 बैच के अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को भी पिता से विरासत में 4 करोड़ कीमत का कमर्शियल लैंड मिली। यह संपत्ति संजीव और उनके भाई के नाम है।

सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को भी मां ने कृषि भूमि खरीदकर उनके नाम की है। इससे उन्हें हर साल करीबन चार लाख रुपए आय होती है ।पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को भी कुरूक्षेत्र हरियाणा में करोड़ों की जमीन विरासत में मिली है। कुरूक्षेत्र में मकान, 3 एकड़ जमीन इसमें शामिल है। उन्होंने खुद अभी तक कोई अचल संपत्ति नहीं जुटाई। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल 2015 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें भी पिता से फ्लैट, मकान और 2 दुकानें विरासत में मिली हैं ।नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना को पिता से गिफ्ट में जयपुर में एक प्लॉट मिला है ।वहीं हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह को पिता से विरासत में 10 एकड़ कृषि भूमि मिली है।

गगनभेदी कामयाबी

नये साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली। इसरो ने 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' यानी स्पेडेक्स के तहत दो उपग्रहों की अंतरिक्ष में डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। इस ऐतिहासिक कामयाबी से भारत अमेरिका,रूस व चीन के बाद यह लक्ष्य हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इस मिशन की कामयाबी से भारत के चंद्रयान-4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे मिशनों का भविष्य तय हुआ है। जहां चंद्रयान-4 मिशन से चंद्रमा की मिट्टी के नमूने भारत लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। दरअसल, स्पेडेक्स दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिये एक किफायती प्रौद्योगिक मिशन है। गत तीस दिसंबर को इसरो ने इस प्रयोग को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके अंतर्गत दो छोटे उपग्रहों को पीएसएलवी सी-60 के जरिये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण के 15 मिनट बाद 220 किलो वजनी दो छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। बीते कल डॉकिंग के बाद एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में स्पेसक्राफ्ट का नियंत्रण सफलता पूर्वक किया गया। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पॉवर स्थानांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल, अंतरिक्ष में डॉकिंग का मतलब है दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। इस डॉकिंग प्रक्रिया को धरती से संचालित किया गया था। कालांतर ये दोनों उपग्रह अपने पेलोड के ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये दो साल तक मूल्यवान डेटा इसरो को भेजते रहेंगे। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, बिना गुरुत्वाकर्षण के बीच तेज गति से घूम रहे उपग्रहों को आपस में जोड़ना बेहद कठिन कार्य होता है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेधा से यह संभव हुआ है।

बहरहाल, इस मिशन की सफलता ने आने वाले समय में गगनयान मिशन, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने व भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्री भेजने के अभियान की सफलता की राह सुगम कर दी है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बाद वहां आने-जाने के लिये भी डॉकिंग तकनीक उपयोगी साबित होगी। वहीं दूसरी ओर सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसान को चंद्रमा पर भेजने के लिये भी यह तकनीक जरूरी थी। निस्संदेह, यह अभियान खासा चुनौतीपूर्ण था। गुरुवार को मिली सफलता से पहले सात और नौ जनवरी को तकनीकी कारणों से इस मिशन को टाला गया था। फिर बारह जनवरी को इसरों ने एक परीक्षण किया था, जिसमें दोनों उपग्रहों को तीन मीटर तक की दूरी तक लाया गया था। इसके बाद आगे के प्रयोगों के लिये सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म विकसित किया। इस बेहद जटिल व संवेदनशील तकनीक को अब तक कामयाब हुए देशों ने भारत को नहीं दिया था। इसीलिए इसरो ने इसे 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' नाम देकर पेटेंट भी करा लिया है। निश्चय ही यह भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि का गौरवशाली क्षण बना है। यह हमारी अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग भी है। वाकई इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। जो आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अतंरिक्ष मिशनों की राह सुगम बनाएगा। निश्चित रूप से अब आने वाले सामरिक व रणनीतिक लक्ष्यों के लिये अंतरिक्ष में कामयाबी निर्णायक साबित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों की यह कामयाबी नई उम्मीद जगाती है। अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिये अमेरिका व चीन में कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है। दोनों चंद्रमा पर अपना वर्चस्व बनाने की होड़ कर रहे हैं। पिछले दिनों चीन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के अंतरिक्ष बल द्वारा जापान में एक इकाई तैनात करने से वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि खुद बीजिंग भी अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। यह भारत के लिये भी चिंता की स्थिति है। ऐसे में भारत को अपने अत्याधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने में कोई ढील नहीं देनी चाहिए।

राज्य के धार्मिक नगरों की पवित्रता बनाए रखने की मुख्यमंत्री मोहन यादव सराहनीय पहल

कृष्णमोहन झा

> “इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के जो संकेत दिए हैं उसमें उन्हें समाज के हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिलने में किंचित मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी एक अप्रैल अर्थात नये वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नयी नीति पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकार धार्मिक स्थलों की पवित्रता अक्षुण्ण होनी चाहिए।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले सवा साल में जिस तरह न केवल सख्त फैसले लिए हैं बल्कि उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है। उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश के सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी को सख्ती से लागू कर सरकार उन धार्मिक नगरों की पवित्रता को बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।”

लगभग सवा साल पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने के तत्काल बाद से ही मोहन यादव ने एक के बाद एक कई सख्त फैसले लेकर यह स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि उनकी कार्यशैली के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।यह सिलसिला पिछले सवा साल से अनवरत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में एक बात और निश्चित रूप से कहीं जा सकती है कि उनके कठोर फैसले भी उनके सात्विक आचार विचार को प्रतिबिंबित करते हैं। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास वाले जिलों में शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की उन्होंने जो सराहनीय पहल की है उसका मूल्यांकन भी इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस स्तुत्य पहल ने उन्हें भूरि भूरि प्रशंसा का हकदार बना दिया है और अब तो यह मांग भी उठने लगी है कि मुख्यमंत्री को संपूर्ण प्रदेश में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के जो संकेत दिए हैं उसमें उन्हें समाज के हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिलने में किंचित मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी एक अप्रैल अर्थात नये वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नयी नीति पर अमल किया जायेगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकार धार्मिक स्थलों की पवित्रता अक्षुण्ण होनी चाहिए।

निकट भविष्य में राज्य के जिन धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है उनमें उज्जैन (महाकालेश्वर मंदिर),अमरकंटक (नर्मदा उदगम स्थल) , महेश्वर(नर्मदा नदी के किनारे प्राचीन मंदिर) ओरछा (रामराजा मंदिर) ओंकारेश्वर (ज्योतिर्लिंग), मंडला (नर्मदा घाट), मुलताई (ताप्ती नदी) , दतिया(पीताम्बरा पीठ) जबलपुर (नर्मदा घाट) , चित्रकूट(रामघाट) ,मैहर (शारदादेवी मंदिर) , सलकनपुर(बीजासन मंदिर) मंडलेश्वर (नर्मदा घाट), मंदसौर(पशुपतिनाथ मंदिर) ,बरमान(नर्मदा घाट) और पन्ना(जुगल किशोर मंदिर) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संतों ने शराब के कारण धार्मिक स्थलों की पवित्रता प्रभावित होने से रोकने के लिए इन धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने हेतु अनुरोध किया था , सरकार उनके सुझावों पर अमल करते हुए ही यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार के इस फैसले से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए इन नगरों की सीमाओं के बाहर शराब दुकानें खोलने की अनुमति देने के बारे में आबकारी अधिकारी मंथन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश के दो पड़ोसी राज्यों बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही जब यह बयान दिया था कि नशा नाश का कारण बनता है तभी से वहां भी शराब बंदी लागू किए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं यद्यपि इस बारे में अभी कोई ठोस फैसला नहीं किया गया है।

गौरतलब है मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राज्य में शराबबंदी की मांग करती रही हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जब नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी तब उन्होंने भी नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में 6 किलोमीटर की सीमा के अंदर शराब और मांस की दुकानें बिक्रीपर रोक लगाने की घोषणा की थी । यहां भी विशेष उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गत वर्ष सितंबर में अधिकारियों को पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसे धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री एवं सेवन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के नये आदेश को गत वर्ष सितंबर में दिये गये उनके आदेश के विस्तारित रूप में देखा जा रहा है। सितंबर में उन्होंने पवित्र नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में शराब और मांस की बिक्री और सेवन रोकने के आदेश दिए थे और अब मुख्यमंत्री ने उसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने की मंशा व्यक्त की है । मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले सवा साल में जिस तरह न केवल सख्त फैसले लिए हैं बल्कि उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश के सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी को सख्ती से लागू कर सरकार उन धार्मिक नगरों की पवित्रता को बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

बीजेपी को दिल्ली चुनाव के बाद मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

अगला कौन ?

रेस में कई दावेदार शामिल

अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी से होगा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी जल्द अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने वाली है। सूत्रों के मुताबिक, 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया है लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यों को चुने जाने से पहले राज्य स्तर पर भी संगठन में परिवर्तन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अगले महीने 10 से 20 फरवरी की बीच नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, जो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। बीजेपी ने हाल ही में अपनी सदस्यता अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है और वर्तमान में राज्य इकाईयों के लिए संगठनात्मक चुनाव कर रही है। इसके बाद ही पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा।

क्या कहता है भाजपा का संविधान?

भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। पदाधिकारियों ने सूत्रों को बताया कि इस बार 10 से 20 फरवरी के बीच पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी तक पार्टी ने इस पद के लिए आधिकारिक तौर पर किसी उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि नड्डा का उत्तराधिकारी या तो कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है या पार्टी के संगठनात्मक ठांचे से कोई व्यक्ति हो सकता है।

1 साल के लिए बढ़ाया गया था नड्डा का कार्यकाल?

फरवरी 2020 में जेपी नड्डा ने अमित शाह से पार्टी की कमान संभाली थी। वैसे तो पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी स्थिर नेतृत्व बनाए रखना चाहती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा के कार्यकाल की एक और बड़ी अचीवमेंट हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक और महाराष्ट्र में मिली शानदार जीत भी है।

आरएसएस का होता है दखल!

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए अध्यक्ष के चयन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन होगा, जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगा लेकिन इसमें आरएसएस की दखल को अहम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के गठन के बाद से बीजेपी हमेशा अपना अध्यक्ष आरएसएस के साथ 'बैठक' के बाद चुनती है, जहां दोनों पक्षों की सहमति से बहुमत समर्थन वाले उम्मीदवार का चयन होता है।

दक्षिण से भी हो सकता है बीजेपी के आगला अध्यक्ष

इसके अलावा एक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार दक्षिण से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है, क्योंकि इस समय पार्टी में दक्षिण का कोई भी नेता बड़े पद पर नहीं है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भाजपा ऐसा कदम उठा सकती है। हालांकि अगर इन सब समीकरणों को अलग रख दें तो शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जैसे नेताओं के नाम भी भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिए जा रहे हैं।

उम्र भी एक बड़ा फैक्टर

भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए उम्र भी एक अहम रोल अदा करेगी, खासकर विपक्ष में युवा नेताओं के उभरने को देखते हुए यह और जरूरी हो जाता है। क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव ऐसे चेहरे हैं जो पार्टियों के मुख्य चेहरे बने हुए हैं और युवा भी हैं। कई बार भाजपा के मौजूदा नेतृत्व को यह आरोप भी झेलना पड़ जाता है कि वो नई नस्ल को बढ़ावा नहीं दे रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार ये कहते हुए सुना जा सकता है कि युवाओं को राजनीति में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए।

बीजेपी संगठन में होगा बड़ा बदलाव

बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष मिलने के साथ-साथ पार्टी के सबसे अहम संगठन महासचिव पद पर नियुक्ति होनी है। बीजेपी में राष्टीय अध्यक्ष के बाद संगठन महासचिव सबसे अधिक ताकतवर माना जाता है। बीएल संतोष बीजेपी के राष्टीय संगठन महासचिव हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब पार्टी नए साल में नए राष्टीय अध्यक्ष के साथ नए संगठन महासचिव की नियुक्ति करनी है। बीजेपी में संगठन महासचिव को संगठन महामंत्री भी कहा जाता है। केंद्र और प्रदेश में संगठन महामंत्री संघ के द्वारा भेजे जाते हैं। ये संघ और भाजपा में समन्वय का काम करते हैं। भाजपा में राष्टीय संगठन महामंत्री आरएसएस का वरिष्ठ प्रचारक होता है, जिसे संघ के द्वारा बीजेपी में भेजा जाता है।बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। यूपी में भूपेंद्र चौधरी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, जिसके लिए कई नाम चर्चा में है। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री बन गए हैं, जिसके चलते अब यहां पर पार्टी को नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सलार भी फडणवीस सरकार में मंत्री बन गए हैं, जिनके जगह भी नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। झारखंड में मिली करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद नए अध्यक्ष की तलाश है।

राजनीति रेस में कई नेता शामिल

बता दें कि, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी से होगा। इसी के साथ अब कई नामों पर भी चर्चा होने लगी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े रेस में बने हुए हैं हालांकि, इस रेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार, विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान के साथ भूपेंद्र यादव का नाम भी तेजी के साथ लिया जा रहा है। ये तीनों ही नेता अमित शाह के करीबी नेता माने जाते हैं। पार्टी के संविधान के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए 15 साल तक पार्टी की सदस्यता होनी जरूरी होती है। साल 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे वहीं, राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 14 तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिसके बाद से अब तक जेपी नड्डा के हाथ में बीजेपी की कमान है।

जाति पर भी दिया जाएगा ध्यान?

सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व नए भाजपा अध्यक्ष का चयन करते समय जाति पर भी ज्यादा ध्यान दे सकती है। क्योंकि नड्डा ब्राह्मण हैं और मोदी अन्य पिछड़ा समुदाय से आते हैं, साथ ही बीआर अंबेडकर के मुद्दे पर घिरने के बाद और खुद पर लगने वाले दलित विरोधी आरोपों को धोने के लिए भाजपा किसी दलित को यह जिम्मेदारी दे सकती है। कांग्रेस ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को आंबेडकर के मुद्दे पर संसद में जमकर घेरा था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित समाज से आते हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस अक्सर भाजपा पर को दलितों की अनदेखी का आरोप लगाती रहती है।

कौन हैं भाजपा के दलित दावेदार?

आंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणियों को लेकर संसद में हुए विवाद के बाद भाजपा के लिए विपक्ष को शांत करने के लिए दलित नेता की नियुक्ति सबसे कारगर तरीका हो सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख उम्मीदवार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य हो सकते हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा, मोदी जी की पिछली पसंद को देखते हुए, वे एक लो-प्रोफाइल नेता और विश्वासपात्र हो सकते हैं। फिर भी उन्हें ऐसा नेता होना चाहिए जो शीर्ष नेतृत्व के विचारों और कार्यक्रमों को लागू कर सके।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

INDIA गठबंधन की कब्र पर खड़ा होगा तीसरा मोर्चा?

कैप्टन बदलने के पक्ष में इंडिया गठबंधन के कई खिलाड़ी!

क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब राहुल गांधी नहीं ममता बनर्जी होंगी? इस सवाल की वजह है इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल को लेकर जारी घटपट है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम- खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडिया गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की कैप्टेंसी में इंडिया गठबंधन के लिए टीम मोदी को हराना असंभव होगा। टीएमसी की मांग है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का कैप्टन बनाया जाए। ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह बंटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर खिलाड़ी कैप्टन बदलने के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लोकसभा में टीम इंडिया गठबंधन का स्कोर है-235 जबकि टीम एनडीए का स्कोर कार्ड है 293। एनडीए के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्षी टीम की कैप्टेंसी को लेकर नई जंग छिड़ गई है। टीएमसी की मांग है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्कोर कार्ड ऐसा है कि अब टीम इंडिया का कप्तान बदलना होगा। कमान बीजेपी के खिलाफ सबसे शानदार चुनावी स्ट्राइक रेट वाली ममता बनर्जी को सौंपनी होगी। मतलब टीम इंडिया में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है।इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों का क्या कहना है, ये जानने से पहले टीएमसी की तरफ से किए गए दावे को समझिए। पहला दावा- कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं। दूसरा दावा- राज्यों में मिली हार के बाद भी कांग्रेस का अहंकार नहीं टूटा। तीसरा दावा- ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। चौथा दावा- बीजेपी के खिलाफ ममता का स्ट्राइक रेट 70 प्रतिशत और राहुल का 10 प्रतिशत। पांचवां दावा- इंडिया गठबंधन नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था।टीएमसी के दावे पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी की पार्टी को आंकड़ों का आइना दिखा रही है। इशारा यही है कि कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं, तो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका राहुल गांधी की है जबकि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या सिर्फ 28 है। यानी टीएमसी से तीन गुना से ज्यादा सांसद कांग्रेस के हैं। नंबर गेम में टीएमसी दूर-दूर तक नहीं है।

यह बात अलग है कि भाजपा इनको निरंतर अप्रासंगिक किये जा रही है और एक के बाद दूसरा राज्य भी इनसे हड़पते जा रही है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वह इन्हें ज्यादा तवज्जो न दे, खासकर चुनाव के पहले। क्योंकि कांग्रेस के वोटबैंक से ही ये खुद को मजबूत करते हैं और फिर उसी को आंख दिखाते हैं। इसलिए कांग्रेस को यदि लंबी राजनीति करनी है तो वह सूबाई और प्रमंडलीय नेतृत्व को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करे। वह विद्वानों और अंग्रेजी भाषी नेताओं से सलाह ले, लेकिन खाँटी राजनीतिक फैसले हिंदी भाषी या क्षेत्रीय भाषा-भाषी और जनाधार वाले नेताओं कहने पर करे, अन्यथा सभ्य शहरी सियासी दलाल उसकी कीमत पर खुद को मजबूत कर लेंगे और उसकी सियासी उद्धार नहीं होने देंगे। कड़वा सच है कि 1977 से ब्रेक के बाद यही देख रहा हूँ। इसलिए अब से भी वह सम्भल जाए। इसके अलावा, सेक्यूलर बनने से ज्यादा व्यवहारिक बने। क्योंकि जबतक वह अल्पमतों को प्रभावित करने वाली राजनीति करेगी, उसे बहुमत कहाँ से मिलेगा, वह खुद सोचे-समझे-फैसले करे।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो राजनीतिक बयानबाजियां होती दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि जहां 'इंडिया गठबंधन' अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वहीं 'एनडीए गठबंधन' पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके अलावा, एक खास लक्षण यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय राजनीति में कभी कद्दावर समझा जाने वाला कांग्रेस-भाजपा विरोधी तीसरा मोर्चा एक बार फिर से अपना नया आकार ग्रहण कर रहा है।राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल परस्पर एकजूट होकर तीसरा मोर्चा पुन: बना लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2029 की राजनीतिक लड़ाई भी त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे जहां भाजपा फायदे में रहेगी, वहीं कांग्रेस को कुछ राज्यों में भारी चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है लेकिन सवाल ये है कि तीसरा मोर्चा बन भी गया तो चलेगा कितने दिन?

ऐसा इसलिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जहां अलग-थलग पड़ चुकी है, वहीं दिल्ली-पंजाब जैसे राज्यों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के पक्ष में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस विरोधी एकजुटता दिखा रहे हैं। इससे लोगों में यह संदेश जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई सत्तारूढ़ पार्टी 'आप' और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच ही होगी। जिसमें अभी तक आप का पलड़ा भारी है, क्योंकि वह सेक्यूलर और हिंदूवादी दोनों सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, जिससे चुनावी समां बंधती जा रही है। वहीं, कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है जिससे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय से जुड़े वोटों में बिखराव तय है। इससे आप को या तो भाजपा के हाथों सत्ता गंवानी पड़ सकती है, या फिर सूबे में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति आती है तो सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि सेक्यूलर सियासत करने के बावजूद आप हिंदूवादी मुद्दों को भी लपक रही है और हिंदुओं को फायदे पहुंचाने वाले फैसले कर रही है, ताकि जो हिन्दू भाजपा-कांग्रेस से नाराज हैं, वो आप की छतरी तले खुद को महफूज समझें। दरअसल, आप को आशंका है कि यदि राष्ट्रीय राजनीतिक ट्रेंड के मुताबिक मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में चले जायेंगे और उसकी प्रतिक्रिया में हिन्दू भाजपा की ओर चले जायेंगे तो उसे भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भाजपा फायदे में रहेगी, वहीं कांग्रेस को नुकसान

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल परस्पर एकजूट होकर तीसरा मोर्चा पुन: बना लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2029 की राजनीतिक लड़ाई भी त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे जहां भाजपा फायदे में रहेगी, वहीं कांग्रेस को कुछ राज्यों में भारी चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व को पता है कि अखिल भारतीय स्तर पर उनकी पार्टी ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है, इसलिए देर सबेर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को मानना पड़ेगा या फिर भाजपा के खेमे में जाना होगा। दरअसल, कांग्रेस के नेतृत्व इंडिया गठबंधन बनने के बाद संयोजक के सवाल पर क्षेत्रीय दलों में जो सिरफुटौव्वल मची, उससे इसके सूत्रधार रहे जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुन: एनडीए की ओर लौटने के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में सम्मानजनक सीट बंटवारे को लेकर जो चूहे-बिल्ली का खेल चला, यह बात भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नागवार गुजरी। तभी आप पार्टी ने हद कर दी थी। एक तरफ तो वह दिल्ली में कांग्रेस के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ पंजाब में दोस्ताना मुकाबले में कांग्रेस से बुरी तरह मात खाई और कांग्रेस से कम सीट ही जीत पाई।

गठबंधन खत्म कर दिया जाना चाहिए

इसके अलावा, कांग्रेस के प्रभाव वाले प्रदेशों में समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, टीएमसी, एनसीपी शरद, शिवसेना यूबीटी आदि क्षेत्रीय दलों ने जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की घुड़दौड़ शुरू की और कांग्रेस विरोधी बयानबाजियों का सहारा लिये, यह बात भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नागवार गुजरी। खासकर जम्मूकश्मीर विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो क्षेत्रीय मुद्दे उठे, कांग्रेस के ऊपर बढ़त हासिल करने वाली कोशिशें हुईं। पारस्परिक टीका-टिपण्णी हुई और फिर ममता बनर्जी को आगे करके राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए गए, उससे यह तय हो गया कि राहुल गांधी के असली राजनीतिक दुश्मन भाजपा नहीं, बल्कि उनके इंडिया गठबंधन में ही मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को तवज्जो देना बंद कर दिया। और तो और, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया (इंडिया) में दिख रही रार के बीच कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दो टूक कह दिया कि, 'लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया (इंडिया) ब्लॉक का गठन किया गया था। कई राज्यों की स्थिति के आधार पर, चाहे वह कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल, वे स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं कि एक साथ लड़ना है या अलग-अलग।' इससे बौखलाए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गठबंधन केवल संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।

कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा...

दरअसल, उमर का पार्टी नैशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और दूसरे दल यह तय करेंगे कि बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा, 'अगर गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए भी है तो हमें एक साथ बैठना होगा और सामूहिक रूप से काम करना होगा।' वहीं, उमर के बयान पर उनके पिता और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत को मजबूत करने और नफरत को खत्म करने के बारे में है। गठबंधन स्थायी है। यह हर दिन और हर पल के लिए है। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन रहे या नहीं रहे, इसको लेकर भी विपक्षी दल असमंजस में हैं। या फिर दो फाड़ हो चुके हैं, अपने-अपने सुविधा के मुताबिक। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबले के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में बने यूपीए, बिहार-यूपी में महागठबंधन और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सियासी हश्र से तो साफ है कि इंडिया गठबंधन का भी देर सबेर वही हश्र होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम 'इंडिया' कहते हैं तो देश के 'अभिजात्य वर्ग' का अहसास मिलता है। जबकि कांग्रेस ने हमेशा 'भारत' यानी गरीब-गुरुबों की राजनीति की है। लिहाजा, उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह यूपीए को जिंदा करके, जिसके मार्फत एक दशक तक देश पर राज कर चुकी है। वहीं, इंडिया को तिरोहित कर दे, क्योंकि इसने ही उसकी लोकसभा चुनाव 2024 की संभावनाओं पर तुषारापात कर दिया। ऐसा इसलिए कि भारतीय राजनीति में चाहे वामपंथी दल हों या समाजवादी दल या फिर दलितवादी दल, ये भरोसेमंद नहीं समझे जाते हैं। वहीं, ओबीसी की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल भी अपनी सियासी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। इनके नेतृत्व में बनने वाला तीसरा मोर्चा 1977, 1989, 1996 में केंद्रीय सत्ता में तो पहुंच गया, लेकिन 5 वर्ष भी अपनी सरकार नहीं चला पाया। क्योंकि इनके डीएनए में आपसी सिरफुटौव्वल है। तीनों बार इन्होंने महज 2-3 वर्षों के दौरान ही दो-दो प्रधानमंत्री दिए और मध्यावधि चुनाव का बोझ भी। इनके बारे में आम धारणा है कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जब ये एनडीए या यूपीए में होते हैं तो वहां भी उलटबांसी करते रहते हैं।हां, राज्यों में इन्होंने 1967, 1977, 1989 और 1996 के सियासी बदलावों का फायदा उठाकर खुद को मजबूत किया। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब आदि इसके सफल उदाहरण दिए जा सकते हैं।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
30 जनवरी 2025

टीम इंडिया 235 सांसद | **कांग्रेस 99 सांसद** | **VS** | **टीएमसी 28 सांसद**

तीसरा मोर्चा कैसा होगा इसकी तस्वीर अभी धुंधली...

लोकसभा के बाद हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे देश की राजनीति में नया विमर्श भी शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति में नए सिरे से ध्रुवीकरण के प्रयास भी शुरू होंगे। हो सकता है कि अभी तुरंत नहीं शुरू हो लेकिन इस साल होने वाले दो विधानसभा चुनावों के बाद निश्चित रूप से विपक्ष में नया ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। इसका पहला संकेत तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को अब अगले चुनाव के लिए ममता बनर्जी को चेहरा मान लेना चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहा कि कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी का चेहरा जनता के बीच काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था। ये वही कल्याण बनर्जी हैं, जो एक समय संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे तो राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे थे। ध्यान रहे हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में कल्याण बनर्जी का कद बढ़ाया है। ऐसे में उनके कहने का मतलब गंभीर है।

ये दिग्गज नेता अभी किसी गठबंधन में नहीं

असल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अच्छा प्रदर्शन करने और उसके बाद राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के बहुत खराब प्रदर्शन की वजह से कुछ स्वाभाविक निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक निष्कर्ष तो यह है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर भाजपा से नहीं लड़ पाती है। जहां भी उसका सीधा मुकाबला भाजपा से होता है वह बुरी तरह से हारती है। दक्षिण के राज्यों का मामला अपवाद है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस अब लगभग पूरी तरह से सहयोगी पार्टियों पर आश्रित हो गई है।तीसरा निष्कर्ष यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का मनोबल लौटा तो उसने सहयोगी पार्टियों को दबाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका अनिवार्य नतीजा महाराष्ट्र की हार है। लोकसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र में शिव सेना ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। गठबंधन में उसको 21, कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 10 सीटें दी गई थीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्ती शिव सेना से ज्यादा सीटें लीं और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया।

यह सही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने हिस्से की 17 में से 13 सीटों पर जीत गई और शिव सेना 21 पर लड़ कर भी सिर्फ नौ ही सीट जीत पाई लेकिन यह अंकगणित का हिसाब है। अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो शिव सेना को महत्व देने का लाभ गठबंधन की दोनों पार्टियों को मिला था। उन्हें शिव सैनिकों के वोट मिले थे। परंतु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अड़ गई कि वह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी क्योंकि लोकसभा में उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है।कांग्रेस की इस जबरदस्ती में सीटों की बंदरबांट हुई। शरद पवार भी जरुरत से ज्यादा सीटें ले गए और उद्धव ठाकरे की शिव सेना को कांग्रेस से नीचे कर दिया गया। कांग्रेस ने दूसरी गलती यह कर दी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। शरद पवार के कहने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। इससे शिव सैनिकों के साथ साथ कट्टर हिंदू वोट भी महाविकास अघाड़ी से दूर हटे और वे भाजपा व उसके गठबंधन के साथ चले गए।

महाराष्ट्र में 75 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला हुआ था। इसमें से कांग्रेस सिर्फ 10 सीट जीत पाई। वह 65 सीटें न सिर्फ हारी, बल्कि उनमें से सात सीटें ऐसी हैं, जिन पर वह दूसरे स्थान पर भी नहीं रही। यानी कम से कम सात सीटों पर महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं माना। इससे पहले हरियाणा में भी आमने सामने के मुकाबले में भाजपा ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस को हराया और अपनी सरकार बनाई। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सिर्फ सात सीट जीत पाई। उसमें भी जम्मू क्षेत्र में जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से था वहां उसे सिर्फ एक सीट मिली। बाकी छह सीटें उसने कश्मीर घाटी में जीती। झारखंड में भी गठबंधन की तीन बड़ी पार्टियों में सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा। वह 30 सीटों पर लड़ी और 16 पर जीती, जबकि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर लड़ कर 34 सीटों पर जीती और राजद ने छह सीटों पर लड़ कर चार पर जीत हासिल की।

लोकसभा और उसके बाद चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से ये निष्कर्ष प्रमाणित हो रहे हैं कि कांग्रेस आमने सामने के मुकाबले में भाजपा को नहीं हरा पाती है, वह सहयोगियों पर आश्रित है और जरा सी ताकत बढ़ती है तो सहयोगियों को दबाने लगती है। तभी विपक्षी पार्टियां अब नए सिरे से ध्रुवीकरण पर विचार करेंगी। कांग्रेस को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने ज्यादा सीटों की मांग नहीं की और अब तक के इतिहास की सबसे कम 328 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई तो उसको इसका बड़ा फायदा मिला। इससे पहले सवा चार सौ सीट लड़ कर वह 50 सीट जीत रही थी तो 328 सीट लड़ कर 99 जीत गई। यह दूसरी पार्टियों के लिए ज्यादा सीट छोड़ने और उनके साथ बेहतर गठबंधन बनाने की वजह से संभव हुआ। लेकिन लोकसभा की जीत ने कांग्रेस का दिमाग खराब कर दिया।उसको लगा कि उसका समय आ गया, जबकि हकीकत यह है कि प्रादेशिक पार्टियों ने अपने संगठन और भाजपा विरोध की अपनी राजनीति में कांग्रेस को पुनर्जीवन दिया है। इसलिए अब वो पार्टियां नए समीकरण पर विचार करेंगी। इस साल दो राज्यों के चुनाव हैं। दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोनों के नतीजों के बाद तीसरे मोर्चे की कवायद तेज होगी। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो वे भी इसकी पहल कर सकते हैं। वे पहले से ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। सबको ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा के बारे में पता है। वे पहले भी तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास कर चुकी हैं। अभी जो विपक्षी गठबंधन है 'इंडिया' उसकी नींव बिहार में पड़ी थी। नीतीश कुमार ने ऐसे गठबंधन की पहल की थी और बिहार में विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक कराई थी। तभी इस साल के चुनाव नतीजों पर नजर रखने की जरुरत है। बिहार से फिर वैसी ही पहल हो सकती है, जैसी 2023 में नीतीश ने की थी।यानी कांग्रेस को साथ रखते हुए एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की। लेकिन इसके अलावा एक संभावना यह है कि कांग्रेस को छोड़ कर विपक्षी पार्टियां तीसरे मोर्चे की पहल करें। इसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर अनिवार्य रूप से होंगे। अखिलेश यादव और जगन मोहन रेड्डी को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के पास राजद, जेएमएम, डीएमके, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिव सेना बचेगी। बहरहाल, तीसरा मोर्चा कैसा होगा इसकी तस्वीर अभी धुंधली है लेकिन चार राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद इसकी रूपरेखा बनने लगी है।

केजरीवाल से आतिशी तक आम आदमी पार्टी दिग्गजों को घर में बीजेपी-कांग्रेस ने घेरा!

आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ने लगाई वादों की बौछार

नई दिल्ली। बीते तीन दशकों में दिल्ली की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। वर्ष 1993 में विधानसभा चुनावों की शुरुआत के बाद अधिकांश बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव में आने से 2013 का चुनाव अपवाद साबित हुआ था। उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसे छोड़ दें तो हर चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया।हर चुनाव में पूर्ण बहुमत देना यह दर्शाता है कि राजधानी की जनता स्थिर सरकार चाहती है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1993 में भाजपा और 1998 से 2008 तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। 2015 और 2020 में आप ने दिल्ली की सियासत में एकछत्र राज किया। 1993 से 2008 के बीच हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती थी। 1993 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस को 14 सीटें मिलीं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय सात सीटों पर काबिज हुए। 1998 से 2008 तक का समय कांग्रेस के लिए स्वर्णिम युग था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का रण सज चुका है। प्रमुख दलों के सेनापति मैदान में उतर चुके हैं। आप और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ज्यों-ज्यों मतदान की तारीखों का समय नजदीक आ रहा, मौसम के नीचे जा रहे पारे के बीच में राजनीतिक पारा चढ़ता दिख रहा है। तीन बार से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इस बार बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी मजबूती से मैदान में डटी है। घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरने की जोरदार कोशिश की गई है। चुनावी रिजल्ट तो जनता के वोट्स पर निर्भर करता है लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल से लेकर आतिशी तक को बीजेपी और कांग्रेस ने घर में ही घेर दिया है।

मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की बीजेपी ने की फील्डिंग

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से विधानसभा चुनाव आप के सिंबल से लड़ रही हैं। यहां से कांग्रेस ने डीयू की पूर्व अध्यक्ष अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया। बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया। रमेश बिधूड़ी, वही हैं जिन्होंने लोकसभा में बसपा के मुस्लिम सांसद पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। 2024 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। रमेश बिधूड़ी 10 साल सांसद रहे हैं।

केजरीवाल को नई दिल्ली में घेरने की क्या सफल होगी रणनीति

दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे अहम चेहरा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। आप पिछले सभी चुनाव केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ी है। 2013 में वह पहली बार नई दिल्ली से विधायक चुने गए थे। उस समय वह तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ ताल ठोकते हुए मैदान में उतरे थे, जनता ने भरपूर समर्थन दिया और केजरीवाल के हाथो तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार तीन बार से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं। इस बार वह चौथी बार यहीं से प्रत्याशी हैं। पर इस बार मुकाबला थोड़ा कठिन होता दिख रहा। कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा है। उधर, बीजेपी ने भी पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दे दिया है। प्रवेश को बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। वह पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल को दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उनके विधानसभा क्षेत्र में ही घेर दिया है। इससे वह अपनी सीट के बाहर राज्य में थोड़ा कम फोकस कर पाएंगे।

बीजेपी के चुनावी वादों के पिटारे में क्या-क्या?

आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की काट के लिए बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान किया है। उसने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो महिला समृद्धि के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजे जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली में भी 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। एलपीजी सिलिंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली पर एक-एक सिलिंडर मुफ्त भी दिया जाएगा। इसके अलावा अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में 5 रुपये में खाना खिलाया जाएगा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। जो बुजुर्ग 70 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। पार्टी ने वादा किया है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, पानी जैसी जो योजनाएं फिलहाल लागू हैं, उसे जारी रखा जाएगा।

आप के इन दिग्गज नेताओं को भी कड़ी चुनौती

आम आदमी पार्टी के एक और सीनियर लीडर व पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवाह को उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है।बाबरपुर सीट से कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के खिलाफ हाजी मोहम्मद इशराक खान को कांग्रेस ने उतारा है। शकूर बस्ती से आप प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉ.सत्येंद्र जैन के खिलाफ सतीश लूथरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है।मेहरौली से आप प्रत्याशी नरेश यादव के खिलाफ पुष्पा सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। यहां से बीजेपी ने नरेश यादव के सजातीय उम्मीदवार गजेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है।दिल्ली में आप के पूर्व नेता और पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। यहां से आप ने देवेंद्र सहरावत को उतारा है। गहलोत की गिनती केजरीवाल के करीबियों में कभी की जाती थी। इसी तरह शीला दीक्षित कैबिनेट का हिस्सा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली को भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारदिया है। वह गांधीनगर सीट से बीजेपी की सिंबल से चुनाव लड़ेगें।

कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति

कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में आक्रामक रुख अपनाया है। पार्टी ने न केवल मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, बल्कि प्रचार अभियान को भी तेज कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं को रैलियों और पदयात्राओं में उतारा गया है। कांग्रेस का फोकस केवल केजरीवाल के खिलाफ प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल की विफलताओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया गया है।पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी, और आतिशी के खिलाफ अलका लांबा जैसे मजबूत नेताओं को खड़ा किया है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेताओं को चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका दी गई है। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख के पीछे कई सियासी कारण हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद कांग्रेस का सियासी आधार लगातार सिमटता गया। 2013 में कांग्रेस को जहां 19% वोट मिले थे, वहीं 2020 तक यह घटकर 4.26% रह गया।दिल्ली में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक- दलित, मुस्लिम, और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मतदाता- आप की ओर शिफ्ट हो गए। कांग्रेस अब इस वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए आप पर पूरी ताकत से हमला कर रही है।

आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों के पिटारे में क्या-क्या?

आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये और बाद में 2100 रुपये देने का वादा किया है। दिल्ली में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को नहीं लागू करने वाली आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा, भले ही सरकारी अस्पताल में इलाज हो या प्राइवेट अस्पताल में। उसने वादा किया है कि उसकी सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के तीर्थाटन जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा पुजारी-ग्रंथी योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18 हजार रुपये वेतन का वादा किया है। ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपये की सहायता का भी पार्टी ने वादा किया है। इसके अलावा उन्हें यूनिफॉर्म के लिए साल में दो बार 2500-2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक नया वादा करते हुए ऐलान किया कि डीटीसी बसों में स्टूडेंट्स के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी।

कांग्रेस भी नहीं पीछे

लोकलुभावन वादों के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने भी प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा पढ़े-लिखे बेरोजगारों को एक साल की अप्रेंटिसशिप और इस दौरान उन्हें हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया है। केंद्र की आयुष्मान योजना या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुफ्त इलाज के वादे की काट करते हुए कांग्रेस ने 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। इसके अलावा मुफ्त राशन किट, 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलिंडर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान किया है।

मिल्कीपुर सीट पर योगी और अखिलेश की सियासी टक्कर

बीजेपी में बगावत की बू, सपा भी अछूती नहीं, चंद्रशेखर से बिगड़ेगा खेल?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अपने सियासी मिजाज में आ गया है। यहां टिकट न मिलने से नाराजगी की भी खबरें हैं। बीजेपी हो या फिर सपा हर जगह बागी मौजूद हैं। ये बागी इस चुनाव में काफी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इनको सहारा कांग्रेस और चंद्रशेखर की पार्टी ने दिया है।अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा संख्या 273 पर उप चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। बीजेपी की तरफ से मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान तो समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद मैदान में हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी के ही बागी कार्यकर्ता सूरज चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं।

मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस उप चुनाव के संग्राम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही बयान बाजी और सियासी पोस्टिंग सभी पार्टियों के भीतर चल रही है। आंतरिक कलह को उजागर कर रहे है, और इस आंतरिक कलह से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल इस हमाम में पूरी तरह शामिल है ।लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर अप्रत्याशित जीत के बाद फैजाबाद लोकसभा से सांसद बने अवधेश प्रसाद का कद समाजवादी पार्टी में और बढ़ गया है। शायद यही कारण था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तय समय से पहले ही अवधेश ने अपने बेटे अजीत प्रसाद की दावेदारी सब के सामने रख दी ।चूंकि अवधेश की जीत से प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति की धार को और रफ़्तार मिली है। लिहाज़ा अखिलेश यादव ने अवधेश के एक निवेदन पर अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा से इंडिया गठबंधन पीडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया।

प्रत्याशी का ऐलान होते ही सपा में बगावत

सपा के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा के बाद मिल्कीपुर से कई वर्षों से विधानसभा सीट से विधायक बनने का सपना सजोए सूरज चौधरी को बागी बना दिया। अजीत के नाम का आधिकारिक तौर पर एलान होने के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफ़ा दे दिया, और मिल्कीपुर विधानसभा में उप चुनाव में चुनावी मैदान में उतर गए ।मीडिया में खबरें चली अवधेश से भी सूरज चौधरी के बागी होने पर सवाल किए गए लेकिन नई नई जीत और सम्मान ने अवधेश की भाषा को असंतुलित कर दिया। अवधेश से जब सवाल किया गया कि सूरज चौधरी ने आप पर वादा खिलाफ और विश्वासघात का आरोप लगाया है तो अवधेश का जवाब था। सूरज चौधरी कौन है मै उनको नहीं जानता हूं।

क्या बोले सपा के बागी सूरज चौधरी?

सूरज चौधरी ने बताया कि वो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में चल रहे थे, लेकिन उसी बीच अवधेश प्रसाद ने सूरज चौधरी से संपर्क किया और सूरज चौधरी को बड़े बड़े सपने दिखाएं ।सूरज का कहना है है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में सूरज चौधरी अपने 5 से 6 हजार कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ मानस पर जा कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद सूरज से अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो उसको प्रदेश की राजनीति में लेकर जाएंगे ।यही नहीं सूरज चौधरी ने अवधेश पर ये भी आरोप लगाया है कि अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने को लेकर उसको 7 बार अपने साथ लखनऊ लेकर गए, लेकिन कभी हॉस्पिटल कभी पार्टी कार्यालय तो कभी किसी अन्य स्थल तक ही सूरज चौधरी का जाना हुआ। लेकिन कभी भी अवधेश प्रसाद ने सूरज को अखिलेश यादव की भेंट नहीं कराया।

मिल्कीपुर सीट सियासी समीकरण

मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहां के उपचुनाव में D-M-Y फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम B-P समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है ।ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित, पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। जिसको साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी है ।मिल्कीपुर

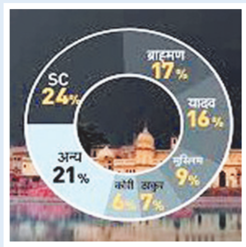

विधानसभा सीट के जीत का मंत्र अगर समझना है तो पहले यहां के जातीय समीकरण को जान लें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3.23 लाख मतदाता हैं। यहां के जातीय समीकरण को देखें तो एक लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटों में करीब 60 हजार सिर्फ पासी समाज का वोट है और 65 हजार यादव मतदाता है। इसके बाद ब्राह्मण 50 हजार, मुस्लिम 35 हजार, ठाकुर 25 हजार, गैर-पासी दलित 50 हजार, मौर्य 8 हजार, चौरासिया 15 हजार, पाल 8 हजार, वैश्य 12 हजार के करीब है। इसके अलावा 30 हजार अन्य जातियों के वोट हैं। जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं और इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के समीकरण समीकरण को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ही पासी समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है तो बीजेपी ने पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभान पासवान को उतारा है। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई बन गई है। दोनों ही नेताओं की नजर पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके चलते स्वाभाविक है कि पासी वोटों में बिखराव होगा।

2024 लोकसभा चुनाव में भी हुआ था अवधेश और सूरज का समझौता

■ सूरज चौधरी और अवधेश का एक बार फिर आपसी समझौता हुआ। वो दौर था 2024 लोकसभा चुनाव का उसमें सूरज चौधरी का आरोप है कि अवधेश ने कहा कि वो सांसद बन गए तो मिल्कीपुर सीट खाली हो जाएगी। उस सीट पर उप चुनाव होगा। लोक सभा चुनाव में सूरज चौधरी ने अवधेश के साथ कदम से कदम मिलकर लोक सभा क्षेत्र में कैंपेन किया, लेकिन फिर एक बार जब अजीत प्रसाद का नाम उप चुनाव में समाजवादी पार्टी से घोषित हुआ तो एक बार फिर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पर कई गम्भीर आरोप लगाते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया ।सूरज अब भी चुनावी मैदान में है और वो इस उप चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा उप चुनाव के प्रत्याशी बनाए गए हैं, सूरज चौधरी का कहना है कि मिल्कीपुर में यादव और पासी समाज के वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अब इसको लेकर सपा-कांग्रेस अलायंस की मुश्किलें बढ़ सकती है।

सपा के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल

■ समाजवादी पार्टी के लिए भी यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, और इस सीट पर भाजपा के खिलाफ सपा ने अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित किया है। सपा के लिए यह चुनौती इसलिए और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि, नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में सपा को निराशा हाथ लगी थी, जहां पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है ।मिल्कीपुर सीट छह महीने से रिक्त पड़ी है, क्योंकि सपा के विधायक अवधेश प्रसाद ने 13 जून, 2024 को इस्तीफा दे दिया था। 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे को छह महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। अब राजनीतिक दलों के लिए यह लड़ाई और भी रोमांचक होने वाली है।

बीजेपी भी बगावत से दूर नहीं

■ बीजेपी में भी बगावत की बू आ रही है। मिल्कीपुर से सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2017 में विधायक चुने गए गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश ने शिकस्त दी थी। जिसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। और गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी को मिले क्षेत्रीय फीडबैक ने गोरखनाथ बाबा के उम्मीदों को तोड़ दिया ।उप चुनाव में चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया है। चंद्रभान पासवान के नामांकन में जिले और प्रदेश के नेताओं ने मंच साझा किया, लेकिन मंच पर गोरखनाथ बाबा नहीं दिखाई दिए ।सूत्रों की मानें तो गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं ने कल देर रात मिले हैं। गोरखनाथ बाबा को केंद्र नेतृत्व का हवाला देते हुए मनाने की हर संभव प्रयास किया है, लेकिन बात कितनी बनी है ये बोलने को कोई तैयार नहीं है ।बीजेपी से नाराज़ चल रहे बीजेपी नेता राधेश्याम त्यागी के भी तेवर ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। राधेश्याम त्यागी के पुत्र ने फेसबुक पर पिता की फोटो पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर जातिगत आंकड़े के तहत फैसले लेने का जिक्र किया है। तो देर शाम ,मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी को उनके आवास पर पहुंच कर की मुलाकात की। उनको मनाने का प्रयास किया है नेताओं ने उप चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए चुनाव में लगने गुजारिश की है।

तेजस्वी यादव को लालू ने सौंप दी विरासत

पटना। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपने का बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे, लेकिन अब पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार भी अब तेजस्वी के पास होगा, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता था। ऐसे में सवाल उठता है कि भैया तेज प्रताप और दोनों दीदी क्या करेंगी ?दरअसल, आरजेडी ने अचानक राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी। पार्टी का सांगठनिक चुनाव चल रहा है, ऐसे में इस तरह की बैठक अप्रत्याशित थी। बैठक का मुख्य एजेंडा पार्टी के संविधान में संशोधन करना था, जिससे तेजस्वी यादव को और अधिकार दिए जा सकें। इस बदलाव से तेजस्वी यादव पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे।

राजद में टूट होने पर पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न और झंडे को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय मान्य नहीं होगा

देश के पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार का वसीयतनामा लिख दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी राजद के संविधान में बदलाव के साथ परिवार के तमाम लोगों के पद और कद तय कर दिए। कहा जा रहा है कि दूसरे दलों में टूट का बारंबार दावा करने वाली पार्टी- राजद को अपना किला बचाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। लेकिन, बात इतनी ही नहीं है। लालू यादव ने पार्टी के अंदर परिवार से उत्तराधिकारी को लेकर सभी संशयों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया। बड़ी बेटी या बेटे को पद दिया, लेकिन कद सभी में छोटे, बेटे तेजस्वी यादव को दिया।

संविधान संशोधन के जरिए देश-विदेश तक संदेश

राजद का संविधान संशोधन लालू परिवार के लिए वक्त की मांग थी। पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और विधान परिषद् में रहने के बावजूद अब ज्यादातर समय पति के आसपास बिताती हैं। उम्र का भी तकाजा है। नई पीढ़ी में बड़ी बेटी मीसा भारती सबसे लंबे समय से राजनीति में हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल रहते जिद पर पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव लड़कर इस बार जीतीं। मीसा भारती का नंबर परिवार में ठीकठाक था, लेकिन उनके बाद वाली बहन रोहिणी आचार्य पिछले दो साल से ज्यादा चर्चा में हैं। किडनी दान कर पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन देने के कारण उनका ग्राफ पार्टी के अंदर तेजी से उछला था। सारण में भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उनका स्वदेश दौरा बार-बार हो रहा है। विदेश से आकर वह विधानसभा चुनाव लड़ें तो अजूबा नहीं। इसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, जो पहले ही छोटे भाई तेजस्वी यादव से कद में छोटे हो चुके हैं। तेज प्रताप दो बार मंत्री बने, जबकि तेजस्वी यादव दोनों बार उप मुख्यमंत्री। इन चार के बीच कुछ हो तो वह घर का मामला है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में लालू के उत्तराधिकारी को लेकर कुछ भी हो तो लंबे अरसे की मेहनत बेकार जाती। इसलिए, पार्टी संविधान में संशोधन के जरिए लकीर खींच दी गई है।

राजद के संविधान का संशोधन क्या कहता है

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बहुत लंबे समय तक नहीं चली। कार्यकारिणी बैठक में दो फैसले लेकर इसे यथाशीघ्र खत्म भी किया जाना था ताकि बहुबात न हो। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के पटना दौरे ने राजद की कार्यकारिणी बैठक को जल्द खत्म करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। जल्दी-जल्दी में वह दोनों फैसले भी हो गए- 1. राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया अक्तूबर में बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले कर लिया जाए। और, 2. परिवार से पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। पहला फैसला कागज पर प्रस्ताव के रूप में आया और दूसरा मौखिक रूप से (बाद में लिखित आने की जानकारी के साथ)। राजद के सांगठनिक चुनाव को अप्रैल से जून के बीच में पूरा किया जाना है, लेकिन इसके साथ-साथ संविधान में संशोधन के जरिए यह तय कर दिया गया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आगे बागडोर नहीं संभाल पाते हैं तो विरासत के उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, न कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव या दूसरे घर जा चुकीं बड़ी बेटियां मीसा भारती या रोहिणी आचार्य।

टूट की बात को आधार बनाने की वजह मौजूद है

अव्वल तो यह कि 'राजद में टूट' की आशंका क्यों है ? इसका जवाब बीच-बीच में मिलता रहा है। पार्टी में एक ही परिवार का वर्चस्व बताकर रामकृपाल यादव जैसे दिग्गज नेता राजद छोड़ चुके हैं। इस समय पार्टी में दूसरा एक परिवार प्रभावी हो रहा था- जगदानंद सिंह का। जगदानंद खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बेटे सुधाकर सिंह सांसद हैं। दूसरे बेटे ने विधायकी का चुनाव लड़ा, हालांकि वह राजद की सीट नहीं बचा सके। जगदानंद नहीं, लेकिन सुधाकर बगावती तेवर के रहे हैं। 28 जनवरी 2024 को लौटी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का 12 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट हुआ तो राजद के कई नेता सत्ता की तरफ हो लिए थे। यह भी एक प्रासंगिक विषय है। इसके अलावा, तेज प्रताप यादव एक बड़ा विषय हैं। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं- 'तेज प्रताप यादव कभी अपना संगठन बनाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव के सारथी बनते हैं और कभी छोटे भाई के आसपास रहने वालों से गुस्सा जाते हैं।

राजद के संविधान में संशोधन वस्तुतः क्या हुआ है?

'राजद में टूट होने पर पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न और झंडे को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय मान्य नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके समकक्ष अधिकार प्राप्त तेजस्वी प्रसाद यादव जो निर्णय लेंगे, वही मान्य होगा।' लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में संविधान संशोधन मूलतः यही है।

तेजस्वी यादव अब जेल भी गए तो भी चलेगी उनकी ही

झारखंड प्रकरण को थोड़ा याद करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाते समय क्या हुआ था ? पिछले साल लगभग इसी समय कल्पना मुर्मू सोरेन अचानक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में सामने आने लगी थीं, क्योंकि हेमंत के जेल जाने की स्थिति में उत्तराधिकारी को लेकर बहुबात हो रही थी। हेमंत ने जेल जाते-जाते पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी देने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन भाभी सीता सोरेन के विरोध ने उन्हें फैसला बदलने को मजबूर कर दिया। आखिरकार चंपाई सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप जेल गए और फिर लौटते ही कुर्सी वापस ले ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी संविधान में हेमंत को यह हक था या नहीं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के पास ऐसा अधिकार रहेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू-राबड़ी के साथ मीसा और तेजस्वी यादव पर भी हमेशा तलवार लटकती रहती है। बीच में ऐसी आशंका के कारण एक बार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का नाम उछला भी था।

पांच बहनें और, लेकिन बिहार की राजनीति से दूर

लालू यादव की नई पीढ़ी में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में हैं। बेटे तो यही दो हैं, लेकिन बेटियां मीसा और रोहिणी के अलावा पांच और हैं। यह पांच बिहार की राजनीति से दूर हैं। रोहिणी के बाद वाली बहन चंदा अपने पायलट पति विक्रम सिंह के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। उसके बाद रागिनी हैं, जो दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से शादी कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। पांचवीं बेटी हेमा के पति विनीत यादव भी राजनीतिक चेहरा हैं, लेकिन बिहार से नाता नहीं रखते हैं। उनके बाद धन्नु उर्फ अनुष्का राव हैं। लालू की बेटी अनुष्का की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव से है। सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में हैं और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पोते पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की पत्नी हैं।

सीएम डॉ. यादव ने केजरीवाल को बताया झूठेलाल...

बोले... सीएम रहते जेल जाकर पूरी दिल्ली की इज्जत खराब की

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'झूठेलाल' कहकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री कुंभ में स्वच्छ गंगा में डुबकी लगाते नजर आए लेकिन क्या केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे जिन्होंने यमुना को साफ स्वच्छ करने का दावा किया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री के पद पर रहते जेल जाने का उदाहरण नहीं है लेकिन कुर्सी के लालच में केजरीवाल ने जेल में रहकर कई महीने सरकार चलाई। उन्होंने लाखों मतदाताओं और पूरी दिल्ली की इज्जत खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्रीकृष्ण और शिशुपाल की कथा सुनाते हुए कहा कि जिस प्रकार कृष्ण ने उंगली उठाकर सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया था। उसी प्रकार आप लोग भी वोटिंग के दिन अपनी उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर केजरीवाल को सत्ता से हटाने का काम करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तुलना राहु-केतू से करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी वजह से दिल्ली में ग्रहण लगा हुआ है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं अब इन दोनों से पीछा छुड़ाना है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश करने का काम इन दोनों दलों ने किया है। जबकि भाजपा नेशन फर्स्ट की भावना से काम करती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहिणी सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉ विजेन्द्र गुप्ता के लिए सभा को संबोधित किया। जनसभा में सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में देश का मान-सम्मान बढाया। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व से हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है।

मोहन के मंत्रियों को मिली स्पेशल पावर

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक देवी अहिल्या बाई के शहर खरगोन के महेश्वर में आयोजित की थी। बैठक में सीएम मोहन और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने अपने मंत्रियों को एक स्पेशल पावर भी दी है। बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में बीते दो सालों से ट्रांसफर पर बैन लगा था। सरकार के नए फैसले के अनुसार प्रदेश में जल्द ट्रांसफर होंगे और अब सरकार के मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेगे। यानि ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आए, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो सरकार के मंत्री ट्रांसफर कर सकते है। जिसके बाद से सरकार के मंत्रियों को ट्रांसफर करने की स्पेशल पावर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से ट्रांसफर कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ था, लेकिन अब नई तबादला नीति आने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में ट्रांसफर को लेकर नई उम्मीद की किरण जागी है। अब संबंधित विभाग में तबादले हो सकेंगे।

उमंग सिंघार ने कसा तंज, कहा...

पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए

मध्यप्रदेश के सीएम मोहन द्वारा प्रदेश में शराब बंदी करने के फैसले से जहां एक तरफ लोगों में खुशी की लहर है तो वही दूसरी तरफ सीएम के इस फैसले से प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर तंज कस्ते हुए कहा कि शहर के नाके के बाहर शराब की दुकानें खोली जाएगी। ये शराबबंदी कहाँ हुई? शराबबंदी करनी है तो जिले में ही क्यों पूरे प्रदेश में करनी चाहिए। उमंग ने आगे कहा कि धार्मिक स्थलों के साथ पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। पहले भी भाजपा सरकार ने नर्मदा किनारे की जगहों पर शराबबंदी की बात की थी। लेकिन 100-200 मीटर पर दुकानें खुल जाती हैं। अब उज्जैन में नाके के बाहर ही खुल जाएगी शराब दुकान। उमंग सिंघार ने आगे कहा कि अगर शराबबंदी करना ही है, तो धार्मिक शहरों के साथ साथ पूरे जिले में होना चाहिए।बता दें कि सीएम मोहन यादव ने हाल ही में शराब बंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि शराब से परिवार के परिवार बराबद हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा कष्ट है। हमने संकल्प लिया है हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग-अलग धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाएगी।

कांग्रेस और नेहरू परिवार पर बरसे मंत्री विजयवर्गीय....

बोले... संविधान को हमेशा पॉकेट में रखा.....

नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू में 'जय बापू जय भीम जय संविधान' सभा को लेकर कांग्रेस और नेहरू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है। हमने सिर पर रखकर सम्मान दिया है, इसलिए कांग्रेस की नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लोग बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेंगे।दरअसल, धार में ध्वजारोहण के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए तो सबसे ज्यादा बाबा साहेब का अपमान किसी ने किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। वह चुनाव लड़े, हराने के लिए उन्होंने उसे जमाने में 20 से 22 सभाएं की। उस चुनाव का परिणाम देख लीजिए। आज भी रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि 74000 वोट निरस्त हुए। यह पहला चुनाव था किसी भी लोकसभा में मुंबई में इतने वोट निरस्त नहीं हुए। यह निरस्त कराए गए हैं।विजयवर्गीय ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। बहुत सारे लोग जेल गए। कांग्रेस के ही लोगों ने उसका विरोध किया था। वह भी जेल में रहे। जितने भी सीनियर लीडर थे, जिसने भी इंदिरा जी का विरोध किया उनको उन्होंने जेल में डाला। यह संविधान का उपयोग उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया या अपने परिवार को बचाने के लिए किया? देश हित में कभी भी नहीं किया।कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर हम राजीव गांधी की बात करें तब सिख दंगे हुए। सिख मारे गए तो राजीव जी से यह पूछा गया कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह क्या उनका संवैधानिक बयान था? चलिए वह छोड़िए इंदौर में शाहबानो महिला थी, उसके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने महिला गुजारा भत्ता देने का घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में वह गए। सुप्रीम कोर्ट के परिणाम को बदल दिया। यह संविधान की हत्या थी, जो राजीव गांधी ने की थी।

उमा भारती ने कहा...

सौरभ शर्मा तो बस एक केंचुआ है... असली अजगर अभी पकड़े जाने बाकी

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेक पोस्ट घोटाले को व्यापमं से भी बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने यह बयान परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर छापेमारी के बाद दिया है।

उमा भारती ने कहा कि अगर एक सिपाही 1,000 करोड़ की संपत्ति बना सकता है, तो सोचिए अफसरों और नेताओं ने कितना कमाया होगा।उमा भारती ने बताया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही चेक पोस्ट बंद करने पर चर्चा शुरू हुई थी। उन्होंने इस बारे में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता गया।उमा भारती ने परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेक पोस्ट घोटाले को व्यापमं घोटाले से भी बड़ा बताया है। उमा भारती का कहना है कि अगर एक सिपाही इतनी संपत्ति बना सकता है तो बड़े अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है।मध्य प्रदेश में 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर मुख्यमंत्री उमा भारती ने तारीफ की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लिखा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के द्वारा 'धार्मिक शहरों में पूर्ण शराब बंदी' अभूतपूर्व निर्णय है। इसके लिए मोहन यादव का अभिनंदन। उन्होंने आगे कहा कि दो साल पहले हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब पर प्रतिबंध नीति बहुत ही जनहितकारी एवं व्यावहारिक थी। हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ही बढ़ रहे थे। यह पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक और कदम है।

अकल चबूतरे से

कुंभ देखो और कुंभ के अजूबे भी देखो

व्यंग्य | **सहीराम**

यह रीलों और वीडियोज का कुंभ है। तरह-तरह के अजूबों का कुंभ है। कुंभ देखो और कुंभ के अजूबे देखो और उनकी और नयी रील बनाओ, वीडियो बनाओ। पहले लोग अपनी नादानी और नासमझी में यह मान लेते थे कि कुंभ मेला सिर्फ दो जुड़वां भाइयों के वहां जाकर बिछुड़ने के लिए ही होता है ताकि एक अच्छी-सी फिल्म बनायी जा सके।

वैसे तो हमारे बेहद प्यारे दोस्त कवि ने 'कुंभ में छूटी औरतें' नाम से एक बड़ी शानदार कविता भी लिखी है।लेकिन यह गंभीर रचनाओं और पीड़ाओं पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। बल्कि अब तो लोग अध्यात्म पर भी कहां चर्चा कर रहे हैं। बस रील और वीडियो बना रहे हैं। बल्कि सच तो यह है कि इधर मामला जिस तरह से एक फिल्म बनाने से आगे निकल कर लाखों-लाख रीलें और वीडियो बनाने तक पहुंच गया है, उससे यही लगता है कि कुंभ मेले ने भी देश की तरह से ही काफी तरक्की कर ली है। फिल्म छोड़ो, अब तो कुंभ मेला सिर्फ रीलें बनाने के लिए ही हो रहा है।टीवी चैनल वाले हांफ रहे हैं, यूट्यूबर्स दौड़ रहे हैं-अरे वो बंजारन मोनालिजा कहां है। अरे वह आईआईटीयन बाबा कहां है। अरे वो औघड़ बाबा कहां है। अरे वो कबूतर वाला बाबा कहां है। अरे वो कांटों पर सोने वाला बाबा कहां है। अरे सुना है उस आईआईटीयन बाबा को जूना अखाड़ा वालों ने निकाल दिया है। कोई कह रहा है वह अभी यहीं था, कोई कह रहा है गांव चला गया है। अरे यार सुना है उसके माता-पिता आए हुए हैं। कहां हैं? वह कुंभ का सर्वव्यापी बाबा बन गया है। कुंभ में आए तमाम साधुओं को उससे रश्क हो सकता है। वह कुंभ पर छा गया है। आह! क्या कमाल का साधु है। वह अपने माता-पिता को गालियां दे रहा है। वाह! वैराग्य हो तो ऐसा हो। जिस धर्म में माता-पिता को भगवान का दर्जा हासिल हो, वहां वह उन्हें अपशब्द कह रहा है, जल्लाद कह रहा है। उसके प्रेम के किस्से भी चल रहे हैं। कोई कह रहा है नशेड़ी है। कोई कह रहा है झगड़ालू है। पागल भी बता रहे हैं। अगर कुंभ में नहीं होता तो जरूर उसे ऐसा पागल मान लिया होता जो ज्यादा पढ़-लिख गया है।लेकिन वह अकेला ऐसा नहीं है। ढूंढ़ो तो ऐसे हजार मिल जाएंगे। कोई अपनी तपस्या के अजीबो-गरीब ढंग से लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो कोई अपने अंग्रेजी ज्ञान से। वहां विदेशी सेलिब्रिटी भी डुबकी लगाते मिल जाएंगे। वहां कोई प्रोफेसर भी मिल जाएगा। वहां अपनी विदेशी गाड़ियों से आए मठाधीश भी मिल जाएंगे। कुंभ अब एक इवेंट है सरकार और नेताओं के लिए। लेकिन लगता है कुंभ का अंतिम सत्य तो रीलें ही हैं। हजारों-लाखों रीलें।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67